पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये बोर्ड का गठन

1588. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या योजना और कार्यक्रम का क्रियान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद जिलों के प्रखण्डों में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय कम है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के लिये एक बोर्ड गठित किये जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध वर्ष 1987–88 के चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति घरेलू खपत के जिलावार आंकड़ों से पता चलता है कि फैजाबाद, गोरखपुर तथा वाराणसी डिविजनों के 14 जिलों में से 10 के आंकड़ें राज्य के अधिकांश जिलों के आंकड़ों के सदृश्य हैं ।

(ख) क्षेत्र तथा आयोजना का विकास और उस प्रयोजन के लिए निधियों का आबंटन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

Joint venture proposals for acquisition of deep sea fishing: trawlers

1589. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether 180 joint venture proposals envisaging acquisition and operation of deep sea fishing trawlers are pending for consideration and decision by Government; and

(b) if so, the reasons for not arriving at a decision as the delay-adversely affects the enormous export potential of deep sea fishing industry?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) Ten proposals for entering into joint venture in deep sea fishing by Indian companies are pending at present. These proposals would be considered by an Empowered Committee of Secretaries in their next meeting. A decision on the propoals will be taken thereafter.

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन लक्ष्य

1590. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2000 के अंत तक 10,000 मेगावाट परमाणु-ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल के आर्थिक संकट के कारण इस लक्ष्य में संशोधन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो परमाणु-ऊर्जा के उत्पादन का अब क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा मार्च, 1991 के अंत में देश में परमाणु-ऊर्जा के उत्पादन की कुल कितने मेगावाट टन की अधिष्ठापित क्षमता थी और क्या यह उत्पादन, क्षमता के अनुरूप रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो वर्ष 1990–91 में क्षमता की तुलना में उत्पादन की प्रतिशतता कितनी थी ; और

(ङ) उत्पादित विद्युत की लागत कितनी होगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) पहले चरण में 10,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता की परमाणु बिजली का उत्पादन प्रधानतः प्राकृतिक यूरेनियम से चलने वाले रिएक्टर लगाकर करने का लक्ष्य अभी भी वही है। इसमें 1000 मेगावाट क्षमता वाले वे दो सोवियत रिएक्टर भी शामिल हैं जिन्हें सोवियत रूस और भारत के बीच हुए अंतःसरकारी सहकार करार, जिस पर नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे, के अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तथापि लक्ष्य प्राप्ति का समय उपलब्ध साधनों पर निर्भर करेगा और जिसे वर्तमान स्थिति के आधार पर सन् 2000 से आगे बढ़ा दिया गया है ।

(ग) सन् 2000 तक के लक्ष्य के बारे में सही स्थिति का पता आठवीं पंचवर्षीय योजना के आबंटनों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही चल सकेगा । वर्तमान स्थापित क्षमता 1465 मेगावाट है। मार्च, 1991 को अधिकतम प्राप्य क्षमता कुछ यूनिटों में नियामक संबंधी प्रतिबन्धों के कारण लगभग 1170 मेगावाट थी ।

(घ) वित्त-वर्ष 1990-91 में राजस्थान बिजलीघर के पहले यूनिट को छोड़कर वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों का कुल वार्षिक क्षमता गुणक स्थापित क्षमता का लगभग 60% था । राजस्थान के पहले यूनिट के प्रचालनात्मक विद्युत स्तर को उसके रिएक्टर के दक्षिणी एंड शील्ड में हुए हल्के पानी के रिसाव को यांत्रिक तरीके से बन्द करने के परिणामस्वरूप 220 मेगावाट की स्थापित क्षमता की तुलना में लगभग 100 मेगावाट तक सीमित कर दिया गया है ।

(ङ) काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों में उत्पादित बिजली पर आई लागत जून, 1991 को लगभग 55 पैसे प्रति किलोवाट से 100 पैसे प्रति किलोवाट के बीच रही। इस लागत में बिजलीघर को 62.8% के मानक क्षमता गुणक पर चलाने से उस पर लगाई गई पूंजी पर हुआ 12% का लाभ और 3.6% का मूल्यह्रास शामिल है ।

पंजाब में कृषि-उत्पादों का प्रसंस्करण

1591. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में उत्पादित विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिये अभी तक यथेष्ट रूप से औद्योगिक क्षमता स्थापित नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गन्ने से चीनी, गेहूं आटा, कपास से धागा और धान से चावल का उत्पादन करने के लिये राज्य की वर्तमान अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने आगामी वर्षों में इस क्षमता को बढ़ाने के लिये कोई व्यापक योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री चिरिंजर गोमांगो) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हल्दिया में उर्वरक उत्पादन इकाई के निर्माण-कार्य का समापन

1592. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगाल में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के अधीन